penditure in the Central Government departments;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what steps nave been taken so far for effecting economy in expenditure and with what results ?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (c) Central Ministries/Departments have been ad vised to eliminate in essential and low priority items of expenditure through a process of prioritisation of their programmes and activities. - Ministries have also been advised to effect economy in expenditure in various areas. These include restrictions on travel expenses, entertainment, internal seminars and conferences, publications, purchase of furniture/furnishing, fuel . consumption, etc. Effect of these j measures is reflected in the Revised Estimates 1989-90 which will be pre-j sented to Parliament alongwilh the Budget for 1990-91.

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति के न्यायाधीश

350. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में इस समय कुल कितने कितने न्यायाधीश हैं और इनमें से कितने-कितने न्यायाधीश अनुसूचित जाति के हैं ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । **(नीचे देखिए)** ।

विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	पदासीन न्यायाधीश	अनुसूचित जाति के न्यायाधीश
1.	इलाहाबाद	46	1
2.	आंध्र प्रदेश	17	—
3.	मुंबई	47	4
4.	कलकत्ता	40	—
5.	दिल्ली	21	—
6.	गुवाहाटी	12	—
7.	गुजरात	12	1
8.	हिमाचल प्रदेश	4	—
9.	जम्मू-कश्मीर	5	—
10.	कर्नाटक	19	1
11.	केरल	24	1
12.	मध्य प्रदेश	22	—
13.	मद्रास	20	1
14.	उड़ीसा	13	—
15.	पटना	28	—
16.	पंजाब और हरियाणा	18	—
17.	राजस्थान	18	—
18.	सिक्किम	2	—
	योग :	368	9